



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127579

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19950 / 2026

मोहम्मद जीशान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: रवि साहू

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आज दायर किया गया पूरक हलफनामा अभिलेख में लिया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि साहू और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
3. यह तत्काल जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 130/2026, धारा 310(2), 317(3) बी.एन.एस., थाना- चकेरी, जिला- कानपुर नगर के तहत आवेदक की जमानत पर रिहाई की मांग के लिए दायर किया गया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उनका कोई सरोकार नहीं है। प्राथमिकी में आवेदक का नाम नहीं था और उनका नाम सह-आरोपी यासीन और मुजाहिद के इकबालिया बयान में सामने आया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तों, नामतः शुभन खान, मुजाहिद और मो. यासीन को इस न्यायालय की एक समकक्ष पीठ द्वारा क्रमशः 07.05.2026, 14.05.2026 और 03.06.2026 के आदेशों के माध्यम से जमानत दी गई है, जो आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 14433/2026, 11900/2026 और 19352/2026 में पारित किए गए थे। उनका आगे यह भी तर्क है कि पूरक हलफनामे के पैराग्राफ संख्या 2, 3 और 4 में आवेदक के आपराधिक इतिहास को अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है और वह 26.02.2026 से जेल में है।

5. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत देने की अर्ज़ी का विरोध किया, हालाँकि वे इस तथ्य को नकार नहीं सके कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-अभियुक्तों - शुभन खान, मुजाहिद और मो. यासीन - को इस न्यायालय की एक अन्य बेंच ने जमानत दे दी है।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

7. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तों, नामतः, शुभन खान, मुजाहिद और मो. यासीन को इस न्यायालय की एक समकक्ष पीठ द्वारा जमानत दी गई है और उक्त आदेशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द या स्थगित नहीं किया गया है, और आवेदक 26.02.2026 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक **मोहम्मद जीशान** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह सबूत पेश करने के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

(ii) आवेदक को विचारण न्यायालय में तय हर तारीख पर खुद या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस वजह के मौजूद नहीं रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ़ आईपीसी की धारा 229-A / बी.एन.एस की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सी.आर.पी.सी. की धारा 82 / बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार आईपीसी की धारा 174-A / बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत उसके खिलाफ़ कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को विचारण न्यायालय के सामने उन तारीखों पर खुद मौजूद रहना होगा जो (1) मामले शुरू करने, (2) आरोप तय करने और (3) सी.आर.पी.सी. की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के लिए तय की गई हैं। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक जान-बूझकर या बिना किसी ठोस वजह के गैर-हाजिर रहा है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल मान सकता है और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, ज़मानत रद्द की जा सकती है।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियों का, गवाहों के बयानों के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में संबंधित विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

16 जून 2026

कीर्ति

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”